SarkariExam.com

11 सितम्बर 2021

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने सरदार इकबाल सिंह लालपुरा

- 10 सितंबर, 2021 को सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। लालपुरा से पहले गैयुरूल हसन रिजवी आयोग के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल पिछले साल मई में पूरा हो गया था।
- लालपुरा 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को विधायी शक्ति मिलने के बाद से इसके अध्यक्ष बनने वाले वाले दूसरे सिख हैं। इससे पहले 2003 में तरलोचन सिंह आयोग के अध्यक्ष बने थे।

❑ **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (The National Commission of Minorities-NCM)**

- अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। अधिनियम के अनुसार, किसी भी मामले की जाँच करते समय आयोग के पास दीवानी अदालत के अधिकार होंगे।
- आयोग में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के साथ-साथ पाँच अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि वे सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हों।

2. DRDO ने भारतीय वायु सेना को सौंपी MRSAM प्रणाली

- 09 सितंबर, 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय वाय सेना

SarkariExam.com

(IAF) को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट (FU) सौंपी है। भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जैसलमेर के वायु सेना स्टेशन में MRSAM को IAF को सौंप दिया गया।

- IAF को सिस्टम सौंपना आत्मानिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग है और यह वायु-रक्षा-प्रणाली में गेम चेंजर साबित होगी।

❑ **मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM)**

- MRSAM एक उन्नत नेटवर्क केंद्रित लड़ाकू वायु रक्षा प्रणाली है। इसे संयुक्त रूप से DRDO और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ-साथ MSMEs से मिलकर भारतीय उद्योग के सहयोग से विकसित किया गया था। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर है। MRSAM कार्यक्रम के लिए अनुबंध पर फरवरी 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस अनुबंध के तहत, IAF ने $2 बिलियन के मूल्य पर 450 MRSAM और 18 फायरिंग यूनिट खरीदने का निर्णय लिया था।
- MRSAM की फायरिंग यूनिट में मिसाइल, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम (MLS), कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS), एडवांस्ड लॉन्ग-रेंज रडार, रीलोडर व्हीकल (RV), मोबाइल पावर सिस्टम (MPS), रडार पावर सिस्टम (RPS) शामिल हैं।
- MRSAM प्रणाली लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी, सब-सोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और अनगाइडेड युद्ध सामग्री आदि जैसे खतरों के खिलाफ जमीनी संपत्तियों के लिए बिंदु और क्षेत्र वायु रक्षा प्रदान करती है।
- यह प्रणाली 70 किलोमीटर तक की दूरी पर कई लक्ष्यों को एंगेज करने में सक्षम है। यह स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट मोटर और नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालित है जो टर्मिनल चरण के दौरान उच्च गतिशीलता प्राप्त करने में मदद करता है।

3. मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु डेनमार्क के सहयोग से बनाएगा ऊर्जा द्वीप

- तमिलनाडु और डेनमार्क राज्य ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप (energy island) बनाने की योजना बनाई है जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण-पूर्वी सिरे के बीच स्थित है।
- यह योजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेनमार्क तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 5-10 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। इसमें मन्नार की खाड़ी में

एक ऊर्जा द्वीप के लिए निवेश भी शामिल है। इस निवेश से द्वीप 4-10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होगा।

- डेनमार्क के विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल ने योजना पर चर्चा के लिए 8 सितंबर, 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। यदि यह योजना अमल में आती है, तो यह भारत का पहला अपतटीय तैरता पवन पार्क (offshore floating wind park) होगा।
- जनवरी 2003 से जनवरी 2021 की अवधि में तमिलनाडु में डेनिश निवेश का मूल्य $751.72 मिलियन अनुमानित है। तमिलनाडु में काम करने वाली कुछ डेनिश कंपनियों में मेर्स्क, वेस्टास, क्यूबिक, डैनफॉस, ग्रंडफोस और एफएलएसमिथ शामिल हैं।

❑ **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड**

- हाल ही में भारत और डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड' का शुभारंभ किया है।
- यह कदम इस लिहाज़ से काफी महत्त्वपूर्ण है कि 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' ने वर्ष 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 30 गीगावाट (GW) क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत अपनी 7,600 किलोमीटर की तटरेखा के साथ विशाल पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके अपतटीय ऊर्जा शुल्कों को कम करने हेतु योजना बना रहा है। यह केंद्र प्रारंभ में चार कार्य समूहों 1) स्थानिक योजना; 2) वित्तीय फ्रेमवर्क की शर्तें; 3) आपूर्ति शृंखला अवसंरचना और 4) मानक एवं परीक्षण पर केंद्रित होगा। प्रारंभिक चरणों में यह 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' केवल अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा, किंतु समय के साथ इसके कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा।
- हरित ऊर्जा हेतु यह प्रयास ऐसे समय में किया जा रहा है, जब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल ने कहा कि चरम मौसम की घटनाएँ भारत और दक्षिण एशिया में जीवन, आजीविका एवं व्यवसायों को काफी अधिक प्रभावित करेंगी।
- ज्ञात हो कि भारत एकमात्र G20 देश है, जिसके द्वारा की जा रही कार्रवाई तापमान में वैश्विक वृद्धि के संबंध में पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप है।

4. 4 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, बनवारी लाल बने पंजाब के गवर्नर

- 09 सितंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सेना उपप्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी

मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। राष्ट्रपति ने बनवारीलाल पुरोहित, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया।

- वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने का अतिरिक्त कार्यभार सौपा है।
- राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उल्लेख किया कि नई नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे।

5. वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप

- हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने ग्रीनलैंड के तट पर एक निर्जन और अज्ञात द्वीप की खोज की है। शोधकर्त्ताओं ने सुझाव दिया है कि इस खोज का नाम 'क्यूकर्टाक अवन्नारलेक' (Qeqertaq Avannarleq) रखा जाए, जिसका अर्थ ग्रीनलैंडिक में "सबसे उत्तरी द्वीप" है।
- इससे पहले उडाक आईलैंड (Oodaaq) को पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था। 60×30 मीटर वाला और समुद्र तल से तीन मीटर की चोटी के साथ यह अब पृथ्वी पर भूमि का नया सबसे उत्तरी टुकड़ा बन गया है।
- इसका निर्माण समुद्र तल की मृदा और मलबे (Moraine) से हुआ है तथा इसमें कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। यह खोज आर्कटिक देशों- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे के बीच उत्तरी ध्रुव के उत्तर में लगभग 700 किमी. तथा आसपास के समुद्र तल, मछली पकड़ने के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने से उजागर मार्गों के नियंत्रण के लिये एक चुनौती के रूप में सामने आई है। ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, हालाँकि नया द्वीप जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है।

6. 09 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस

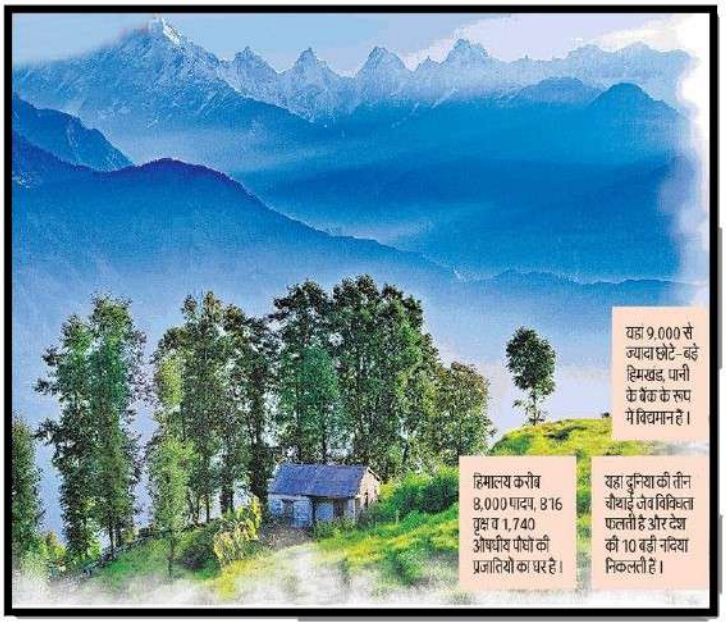

- 09 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नौला फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में हिमालय दिवस 2021 मनाया गया है। इस इसकी थीम 'हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां' है। यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है।
- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने हिमालय के महत्व को समझाया और हिमालय में अनियोजित शहरीकरण पर चिंता जताई है।
- उन्होंने कहा है कि खराब निर्माण योजना और डिजाइन, खराब बुनियादी ढांचे वाली सड़कों, सीवरेज, पानी की आपूर्ति आदि और पेड़ों की अभूतपूर्व कटाई के कारण हिमालयी पहाड़ी शहरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

7. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया गया एक विशेष अभियान 'मैं भी डिजिटल 3.0'

- 09 सितंबर, 2021 को देश के 223 शहरों में 'मैं भी डिजिटल 3.0' को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। यह पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान है।
- यह अभियान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया है। इस अभियान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर QR-Code का उपयोग कर भुगतान प्राप्त करने और विक्रेताओं से खरीदी गई सामग्री का भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसमें रेहड़ी-पटरी वालों को डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण एक सुरक्षित मंच के माध्यम से प्रदान किया जाना है।

❑ **पीएम स्वनिधि योजना**

- जून, 2020 में 'केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय' द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (The Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

8. हैदराबाद में हुआ भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन

- हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) अनुसंधान एवं विकास केंद्र, हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र (High Ash Coal Gasification Based Methanol Production Plant) का उद्घाटन किया है।
- परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने नीति आयोग, पीएमओ-भारत और कोयला मंत्रालय की पहल पर 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया था।

- यह संयंत्र 1.2 टीपीडी फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रति दिन (टीपीडी) मेथनॉल बना सकती है। उत्पादित कच्चे मेथनॉल की शुद्धता 98 से 99.5 प्रतिशत के बीच होती है।

❑ **मेथनॉल**

- मेथनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में, जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मेथनॉल का उपयोग डी-मिथाइल ईथर (डीएमई) उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, एक तरल ईंधन जो डीजल के समान होता है - मौजूदा डीजल इंजनों को डीजल के बजाय डीएमई का उपयोग करने के लिए न्यूनतम रूप से बदलने की आवश्यकता होती है।

9. तेलंगाना में आज लॉन्च किया जाएगा 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' प्रोग्राम

- तेलंगाना सरकार का 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' कार्यक्रम 11 सितंबर, 2021 को लॉन्च होने के लिये पूरी तरह तैयार है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में चिकित्सा आपूर्ति शृंखला में सुधार हेतु वितरण के एक मोड के रूप में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में वितरण केंद्रों से विशिष्ट स्थानों तक दवा पहुँचाने में ड्रोन प्रोद्योगिकी की मज़बूती और विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाएगा। इसके माध्यम से दवाओं, टीकों, रक्त की इकाइयों, नैदानिक नमूनों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की डिलीवरी की जा सकेगी।
- यह आगे नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य प्रणालियों को ड्रोन वितरण के अवसरों और चुनौतियों के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी वितरण मॉडल और प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण करने में सहायता करने का इरादा रखता है।
- इस परियोजना का नेतृत्व 'विश्व आर्थिक मंच', 'नीति आयोग' और 'हेल्थनेट ग्लोबल' (अपोलो हॉस्पिटल्स) के साथ साझेदारी में तेलंगाना सरकार के आईटी विभाग के तहत 'इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ विंग' द्वारा किया जा रहा है और इसका लक्ष्य 'बियॉन्ड विज़ुअल लाइन ऑफ साइट' (BVLOS) ड्रोन उड़ान शुरू करना है।

10. बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म 'बॉब वर्ल्ड'

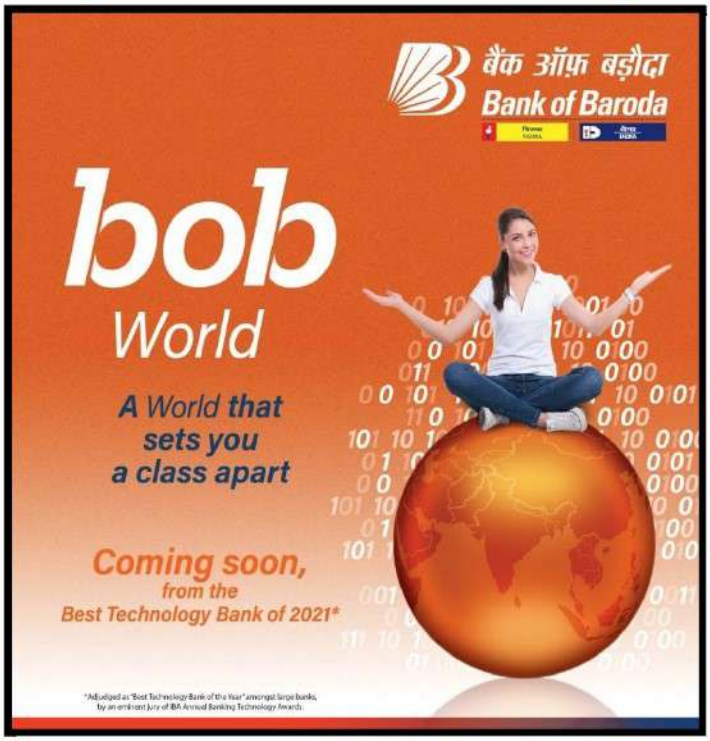

- हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 'बॉब वर्ल्ड' नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्लेटफ़ॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त, 2021 को शुरू हुआ।
- 220 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लगभग 95 प्रतिशत शामिल होगा, जिसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
- बॉब वर्ल्ड' चार प्रमुख बिंदु - सेव, इन्वेस्ट, बॉरो एंड शॉप के तहत चरणों में शुरू किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा।
- इसने ग्राहकों को एक छत के नीचे बैंकिंग और उससे आगे का एक संपूर्ण और फायदेमंद अनुभव प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स को भी एकीकृत किया है।